भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1889

19.12.2022 को उत्तर के लिए

पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन

1889. श्री सु. थिरूनवुक्करासर :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में गुजरात में पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा के लिए उठाए गए मुद्दों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 2026 तक शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लक्ष्य को संशोधित करके 40 प्रतिशत कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा है और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 23-24 सितंबर 2022 के दौरान एकता नगर, गुजरात में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में पर्यावरण के लिए जीवन शैली (एलआईएफई) जलवायु परिवर्तन से निपटना, परिवेश [एकीकृत हरित स्वीकृतियों के लिए एक एकल विंडो प्रणाली], कृषि वानिकी, प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, जैव विविधता सहित वन्यजीव प्रबंधन और नमभूमि के संरक्षण और प्लास्टिक और अपशिष्ट प्रबंधन पर लक्षित विषयों के साथ छह विषयगत सत्र थे।

(ग) और (घ) पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए एक दीर्घकालिक, समयबद्ध, राष्ट्रीय स्तर की कार्यनीति है। एनसीएपी में वर्ष 2017 को आधार वर्ष बनाकर वर्ष 2024 तक विविक्त कण (PM10) सांद्रता के संदर्भ में 131 शहरों में वायु प्रदूषण को 20-30% तक कम करने की परिकल्पना की गई है। एनसीएपी को वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है और लक्ष्यों को संशोधित कर 40% कर दिया गया है। एनसीएपी कार्यनीति में स्रोत विशिष्ट उपशमन कार्रवाइयों के लिए राष्ट्रीय, राज्य और शहरी स्तरों पर स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन, वायु गुणवत्ता सुधार निष्पादन से जुड़े लक्षित शहरों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन संरचना, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा समन्वित कार्रवाई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों की योजनाओं से संसाधनों का अभिसरण और एक जन आंदोलन (जन आंदोलन) का निर्माण शामिल है। एनसीएपी के तहत की गई कार्रवाइयों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

***

अनुबंध

'पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन' के संबंध में श्री सु. थिरूनवुक्करासर द्वारा दिनांक 19.12.2022 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1889 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत की गई कार्रवाई का विवरण

एनसीएपी के तहत कार्य योजनाएं:

1. राष्ट्रीय स्तर की योजना तैयार करने में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं/कार्यक्रमों का अभिसरण शामिल है।
2. 24 राज्यों में राज्य कार्ययोजनाओं की तैयारी।
3. 131 शहरों में शहरी स्तर की कार्ययोजनाओं की तैयारी।

दिशानिर्देश:

4. एनसीएपी के तहत 82 शहरों के लिए निधियों को जारी करने और उसे उपयोग करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए।
5. 49 शहरों के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित मिलियन प्लस सिटी चैलेंज फंड की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए संचालन दिशानिर्देश जारी किए।
6. वायु गुणवत्ता प्रबंधन के संबंध में राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर पर जागरूकता और पब्लिक आउटरीच कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए क्षमता निर्माण और आउटरीच कार्यक्रमों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।
7. वायु गुणवत्ता में सुधार के उपाय करने के लिए शहरों को रैंक करने के लिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण (शहरों का रैंकिंग) पर दिशानिर्देश जारी किए।
8. एनसीएपी के तहत गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और शहरों को तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) और प्रतिष्ठित संस्थान (आईओआर) के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए।

निगरानी और कार्यान्वयन:

9. एनसीएपी की प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तरीय समितियां गठित की गईं:

    क) शीर्ष समिति

    ख) संचालन समिति

    ग) निगरानी समिति

    घ) कार्यान्वयन समिति

10. एनसीएपी गतिविधियों की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समितियां गठित की गई:

    क) संचालन समिति

    ख) राज्य स्तरीय निगरानी और कार्यान्वयन समिति

    ग) जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति

11. एनसीएपी दिशानिर्देशों के अनुरूप गतिविधियों को करने के लिए शहर स्तरीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्रकोष्ठों का गठन किया गया है।

12. वायु गुणवत्ता में सुधार के उपाय करने के लिए 82 शहरों के लिए सीपीसीबी, एसपीसीबी और यूएलबी और 49 शहरों के लिए एमओईएफसीसी, राज्य सरकार और यूएलबी के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

13. एमओईएफ एंड सीसी ने एनसीएपी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए "प्राण" नामक एक पोर्टल भी शुरू किया है।

14. राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) जिसमें आईआईटी, अनुसंधान संगठनों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से विशेषज्ञ, स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल हैं, का गठन एनसीएपी के तहत गतिविधियों का समर्थन करने के लिए संस्थानों का एक बड़ा सामूहिक पूल बनाने के लिए स्थानीय तकनीकी क्षमताओं का निर्माण करने की दृष्टि से किया गया है।

15. शहर की कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए 131 शहरों को 88 प्रतिष्ठित संस्थानों (आईओआर) को सौंपा गया है।

<u>निधियों की स्वीकृति:</u>

16. वायु गुणवत्ता में सुधार करने के उपाय करने के लिए शहर की कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2021-22 तक 131 शहरों को 6897 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

17. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 131 शहरों को 2985.6 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 82 शहरों के लिए 290 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं (30 नवंबर, 2022 तक)।

<u>जन जागरूकता और क्षमता निर्माण:</u>

18. एमओईएफ एंड सीसी ने हितधारकों की जागरूकता, ज्ञान साझा करने और क्षमता निर्माण के लिए निम्नलिखित कार्यशालाओं का आयोजन किया:

    क. वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए पश्चिमी क्षेत्र के लिए मुंबई में 22 और 23 नवंबर 2021 को **कार्यशाला आयोजित** की गई और एनसीएपी और 15वें वित्त आयोग अनुदान के विषय में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा राज्यों को सुग्राही बनाया गया।

    ख. दक्षिणी क्षेत्र के लिए, चेन्नई, तमिलनाडु में 21 और 22 मई 2022 को कार्यशाला आयोजित की गई और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, अंडमान और

निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन और दीव राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुग्राही बनाया गया।

ग. दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र के लिए, दिल्ली और एनसीआर की वायु गुणवत्ता के मुद्दे पर दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र सहित गुरुग्राम, हरियाणा में 7 और 8 मार्च, 2022 को "स्वच्छ वायु के संबंध में वार्ता" संबंधी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

घ. भुवनेश्वर, ओडिशा में 3 और 4 दिसंबर, 2022 को राष्ट्रीय वायु सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी 131 शहरों को शामिल किया गया और जिसमें एनसीएपी के कार्यान्वयन के लिए वैज्ञानिक ज्ञान और उत्तम पद्धतियों को साझा करने के लिए पूरे देश से वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, शिक्षाविद, परामर्शी, विद्यार्थी और अन्य हितधारक शामिल हुए।

19. चेन्नई, तमिलनाडु में 26-27, 2022 को 'इको अल्टरनेटिव एक्सपो एंड स्टार्ट-अप कॉन्फ्रेंस' के दौरान वायु गुणवत्ता प्रबंधन के क्षेत्र में स्टार्ट-अप्स की कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनी आयोजित की गई है।

20. "स्वच्छ वायु सर्वेक्षण" के अंतर्गत नौ (9) शहरों को 5.25 करोड़ रूपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया।

21. वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान वायु गुणवत्ता प्रबंधन के संबंध में कार्यशालाएं और पब्लिक आउटरीच कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए राज्यों को 1 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

22. वायु प्रदूषण उपशमन प्रौद्योगिकियों के मूल्यांकन के लिए दिल्ली में प्रायोगिक अध्ययन शुरू किए हैं। आनंदविहार, आईएसबीटी में 01 अक्टूबर, 2021 को वायु प्रदूषण में स्थानीय रूप से कमी लाने के लिए एक प्रायोगिक स्मॉग टावर स्थापित किया गया है।

***